Chambers of Commerce and Industries (FICCI) urging to initiate multi-proriged comprehensive strategy for promotion of agriculture sector.

(b) A background paper was prepared by FICCI for discussion in a Seminar on "Strategies for Promotion of Dry Land Crops", conducted by them on 20.7.1996. The discussion paper inter-alia includes the following:—

(i) Improvement in productivity in rainfed and dry land areas.

(ii) Popularisation of high-yielding varieties of seeds particularly suitable for dryland areas,

(iii) Inter-cropping and suitable crop mixture,

(iv) Water management,

(v) Diversification of less water consuming crops,

(vi) Research and Development in important dryland crops like pulses, coarse grains, cotton, oilseeds, etc.

(c) The Government is seized of the issues and these points are kept in view while formulating programmes for agricultural development.

कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति

2620. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर पिछड़े जिलों में कृषि-आधारित उद्योगों की पर्याप्त संख्या में स्थापना तथा उनको तेजी से प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार, देश में स्थापित कृषि आधारित उद्योगों का राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य और गैर-खाद्य दोनों उद्योग शामिल हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अनाज तथा दलहन प्रसंस्करण उद्योग, फल एवं सब्जी, गोश्त, मछली तथा कुक्कुट प्रसंस्करण उद्योग, चीनी, खाद्य तेल, रोपण फसलें जैसे चाय, कॉफी अल्कोहल आदि शामिल हैं। कृषि पर आधारित गैर खाद्य उद्योगों में फटसन और पेस्त्र आधारित उद्योग, कपास वस्त्र, रेशमपालन उद्योग, पशुआहार, कुक्कुट और मछली आहार, पेपर तथा सम्बद्ध उत्पादन, जड़ीबूटियों से औषधियों का विनिर्माण आदि शामिल है।

कृषि नीति संकल्प के प्रारूप में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है, इससे कृषि उत्पाद के कारगर उपयोग तथा उत्पादन आधार के सन्निकट मूल्य वर्धक सुविधाएं सृजित करने पर जोर दिया जाएगा ताकि वास्तविक उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

कृषि नीति के प्रारूप को संसद सदस्यों और सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सरकार, सरकारी / सरकारी समितियों, सहकारी संगठनों [illegible] को उपलब्धता देकर कृषि आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देती है। सरकार किसानों के लिंकेजों के विकास, विपणन सहायता, भण्डारण पैकिंग, मानवशक्ति का प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास के लिए भी मदद करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। घरेलू / विदेशी / अनिवासी भारतीय निवेशों को वित्तीय राहतों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। उत्तरपूर्वी क्षेत्रों सहित पिछड़े इलाकों में अधिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फल व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र तथा गोश्त और कुक्कुट प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

कृषि आधारित उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए प्रत्येक राज्य में ऐसे उद्योगों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है।

Reduction in the price of Pentoxifylline

2621. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of CHEMICAL AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Department of Chemicals, while fixing the local bulk